

ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal
प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 26, अंक 249

जुलाई 2024



तरमै श्री गुरुवे नमः

संपादक – डॉ. तारा परमार



भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

संस्थापक सम्पादक

डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक

सेवाराम खाण्डेकर

11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श

आयु. सूरज डामोर IAS

पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक

डॉ. तारा परमार

9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :

डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली

डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात

डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात

डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee

डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)

प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)

प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)

डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार

श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	3
2	"Beyond Borders : Dr. Babasaheb Ambedkar's Reflections on Pakistan	Ms. Sujata Balvant Shirode Research Scholar	4
3	Integrating ICT in ECCE-Status, Challenges, and Prospects with Special Reference to Selected Schools of Patna	- Mohd Gufran Barkati - Dr. Jarrar Ahamad - Md Arif Equbal	9
4	शिक्षा और जागरुकता : डॉ. अम्बेडकर	डॉ. ललिता कौशल	13
5	Employee Relations and HRM: Critical Role in Fostering Sustainability in MSME Sectors	Dr. Sudipta Adhikary	17
5	A Study of Principals' Administrative Effectiveness and Their Institutional Academic Performance	Dr. Mohan Lal 'Arya' Professor - Gaurav Kumar Research Scholar	21

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)

खाते का नं.- 63040357829

बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,

शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)

IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com

E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

अपनी बात

मनुष्य के अस्तित्व के लिए पर्यावरण उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार उन्नत जीवन के लिए आर्थिक विकास। इकॉनामी और इकालॉजी का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारतीयों का प्रकृति-वन, पेड़-पौधों से गहरा संबंध रहा है। हमारी संस्कृति का मूल आधार यह है कि "हम पोषण कर सकते हैं, लेकिन शोषण व विध्वंस नहीं।" दोहन से पूर्व और उपरांत पोषण से संतुलन बना रहता है, लेकिन दोहन बगैर पोषण के शोषण होकर विध्वंस वाली स्थिति बन जाती है।

प्रकृति के साथ "सहजीवन व सहअस्तित्व" की बात करनेवाला मनुष्य कालांतर में प्रकृति को उपभोग की वस्तु के रूप में काम में लेने लगा। परिणामस्वरूप प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में असंतुलन इतना हो गया कि आज वह हमारे सामने चुनौती के रूप में है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हमारे यहाँ सिद्धांत और व्यवहार के बीच गहरी खाई है। सामाजिक धरातल पर आदर्शों और सरकार के स्तर पर कानूनों की भरमार है लेकिन न तो आदर्शों का पालन ही होता है और न कानूनों का। पर्यावरण की अवधारणा बहुत व्यापक और सर्व समेटू है। हमारे आसपास जो कुछ है, वह सब पर्यावरण ही तो है। हम भूमि का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा करने वाले वन और पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई रूक नहीं पा रही हैं जल का भी यही हाल है, उसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है जिसके कारण भू-जल स्तर रसातल में खिसकता जा रहा है। पर्यावरण की समस्या अत्यधिक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं बल्कि विकास की अपूर्णता का द्योतक है। एक जानकारी के अनुसार समाजशास्त्रीय अवधारणा है कि हजारों वर्षों की सभ्यता समाप्त होने में बहुत कम समय लगता है (चंद्र घण्टे), यदि जीवों को भोजन नहीं मिले। मानव चेतना, नैतिकता, धर्म, दर्शन, विकास, संस्थाएं आदि तभी तक हैं जब तक यह विश्वास हो कि भविष्य में भोजन पर कोई खतरा नहीं हो। तापमान और कृषि उपज में विपरीत संबंध है।

ओशो कहते हैं—“आप वृक्षों को काटते चले जाते हैं बिना फिक्र किये हुए, लेकिन अब घबराहट पैदा हो रही है। क्योंकि आपने बहुत वृक्ष काट डाले जमीन से। उसे पता ही नहीं है कि वृक्ष के बिना जमीन नहीं हो सकती क्योंकि वृक्ष अनिवार्य है, आपके जीवन के लिये। वृक्ष सूरज की किरणों को पीता है, इस जमीन पर कोई और चीज उनको नहीं पी सकती। वृक्ष पीकर उसे विटामिन-डी बना देता है। यह 'डी' विटामिन जीवन के लिये बिल्कुल अनिवार्य है। यदि वृक्ष कम होते चले जाए-डी विटामिन कम हो जाय। आदमी मुश्किल में पड़ जाए, पक्षी मुश्किल में पड़ जाए।

आप वृक्ष काटते चले गये, आप अपने जीवन का एक अंग काटते चले गये। अब अड़चन शुरू हो रही है। वृक्ष है तो बादलों को वृक्ष आकर्षित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, उनकी प्यास बुलाती है, खींचती है। उनकी ठंडक बादलों को अपने पास ले लेती है, बादल उनसे आनंदित उन पर वर्षा कर जाते हैं। वृक्ष काट देते हैं हम, बादल चले जाते हैं। आप नीचे खड़े देखते रहते हैं कि कब वर्षा हो, लेकिन आपके लिये बादल कभी नहीं आये थे। आपसे उनका सीधा कोई संबंध नहीं है, आपका उनसे संबंध वृक्षों के द्वारा है-वाया मीडिया। आदमी से बादलों का कोई लेना-देना नहीं है। बादल आदमी की कोई आवाज नहीं सुनते, आप कितना ही इन्द्र देवता को बुलाओ। आपकी बात सुनेंगे कैसे, बादलों को आदमी की भाषा आती ही नहीं है। हाँ, जब वृक्ष उनको बुलाते हैं तो वे आते हैं।”

निःसंदेह कृषि खुले में होती है और मौसम-सापेक्ष है, यदि औसत तापमान दो डिग्री भी बढ़ जाए तो दुनिया में गेहूँ, धान, दलहन, तिलहन के उत्पादन में दस प्रतिशत का अंतर आ सकता है। कृषि क्षेत्र जो प्रायः जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला शिकार होता है-इस संकट में सबसे आगे है। भारत के किसान पहले ही मौसम की अनिश्चितता से परेशान थे और अब तो वे बढ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

- डॉ. तारा परमार

"Beyond Borders : Dr. Babasaheb Ambedkar's Reflections on Pakistan"

Ms. Sujata Balvant Shirode
(Scholar)

["Pakistan is merely another manifestation of cultural unit demanding freedom for the growth of its own distinctive culture- Dr. B.R. Ambedkar"]

Abstract:

Dr. B.R. Ambedkar's multidimensional perspective on the partition of India and the creation of Pakistan defined in his influential book "Pakistan or the Partition of India," reflects his deep concern for religious minority's rights and social justice. While addressing historical factors, he expressed reservations about the partition, fearing displacement, religious intolerance and instability. Dr. Ambedkar imagined a progressive, secular Pakistan but remained skeptical highlighting social reforms, education, economic development and minority rights. His insights offer valuable lessons for contemporary challenges in building impartial and justifiable societies emphasizing tolerance and respect for human rights. This article explores into Dr. Ambedkar's thoughts on Pakistan exploring his analysis of the historical

context, the foundation for partition and the future of the newly formed nation.

Introduction :

Dr. Babasaheb Ambedkar, a prominent social reformer, jurist had a multifaceted perspective on various socio-political issues. He played a key role in India's independence struggle and the framing of the Indian constitution. He is known as sculptor of the Indian Constitution. Dr. Ambedkar was a religious man but never advocated hypocrisy in the name of religion. For him religion was morality and it should effect the life of each individual's character, actions, reactions, likes and dislikes. His views on the partition of India and the subsequent creation of Pakistan offer a unique perspective shaped by social dynamics, historical context and his commitment to the principles of justice and equality. In his important work, 'Pakistan or the Partition of India', first published in 1940, Dr Ambedkar observed the issue of Pakistan.

Historical Context and Reasons for Partition :

Dr. Ambedkar's thoughts on the partition were grounded on the socio-political complexities of pre-independent India. He observed increasing communal tensions between Hindus and Muslims which were aggravated by the British strategy of "divide and rule." In his publication, "Pakistan or the Partition of India," Dr. Ambedkar agreed that the call for a separate Muslim state was an outcome of the "two-nation theory," which perceived Hindus and Muslims as distinct communities. While admitting historical factors, he predicted that partition would cause extensive displacement, sensitive religious enmity and the emergence of two weak states. While seeing Muslim League's politics over religion he warned against "Religious Nationalism." He advocated that political arrangements should be done on basis of economic interests not on religious affiliations. Dr. B. R. Ambedkar's stand on the Partition of India in 1947 was complex and evolved over time. He initially supported the creation of a separate Muslim state but later became critical of the way it was carried out and the subsequent treatment of minorities in Pakistan. Muslim League campaigned for demand of Pakistan which resulted into establishment of India and Pakistan along with extensive

communal violence and mass migrations followed by substantial human suffering.

Rights of Religious Minorities :

Dr. Ambedkar's primary concern regarding the partition was the fate of minorities in both India and Pakistan. He feared that religious majorities would differentiate against and disrespect their minority counterparts. In Constituent Assembly of India he warned about the potential dangers of Hindu majority advising them to ensure the protection of religious minorities through Constitutional safeguards. Dr. Ambedkar discussed the specific challenges faced by the Muslim minority in India and the Hindu minority in Pakistan in his writings. He argues that both groups would be vulnerable to discrimination and oppression. Thus their political and cultural rights would be under constant threat. Dr. Ambedkar believed in the protection of the rights of religious minorities, irrespective of the majority religion in a country. His vision for India was preserved in the Indian Constitution, which guaranteed Fundamental Rights to all citizens, regardless of their religious or social background. Ambedkar's concerns regarding the status of minorities in Pakistan reflected his commitment to these principles.

Vision for Pakistan :

Despite his reservations about the partition, Dr. Ambedkar hoped that Pakistan would become a progressive and democratic state. He increasingly emphasized the importance of secularism as a key principle for any nation including Pakistan. He argued that religion should not be the ground for governance and that all citizens should be treated equally regardless of their religion. He believed that it was essential for Pakistan to develop a secular constitution that would safeguard equal rights to all citizens irrespective of their religion. He also emphasized the importance of economic development and social reforms in building a strong and prosperous nation. Dr. Ambedkar strongly recommended that India and Pakistan should try to maintain cordial relations and cooperate on issues of mutual interest. He visualized a future where both nations could coexist peacefully and contribute to the development of the region mutually.

Future Concerns :

Dr. Ambedkar expressed disbelief about the idea of Pakistan particularly in relation to the status of minorities within the new nation. As a defender of the rights of marginalized communities, he was concerned about the fate of religious and

ethnic minorities, especially Hindus, Sikhs, and Dalits in the newly formed Pakistan. He predicted potential challenges in implementing principles of equality and justice, particularly for minorities, in a state that was explicitly created for one religious community. Dr. Ambedkar was cautious of the impact of a theocratic state on the rights and freedoms of individuals belonging to minority groups. His thoughts on Pakistan were also influenced by his commitment to social justice and the upliftment of marginalized communities. He recognized that the creation of a separate nation based on religion could potentially marginalize minority groups within that nation. He highlighted on the principles of liberty, equality and fraternity to overcome partition's impact on various communities. Though Ambedkar had reservations about the creation of Pakistan, he was aware of the political realities of the time. He recognized that the partition was an irreversible historical process and despite his concerns advocated for the protection of the rights of minorities in both India and Pakistan.

Recommendations to Pakistan as Progressive Nation :

Dr. Ambedkar aspired to see Pakistan as a modern, democratic, and

progressive nation post-partition. He dreamed of a state where Secularism would prevail. He strongly believed that a secular constitution, assuring equal rights and freedom to all citizens regardless of religion was essential for building a stable and inclusive society. Social justice would be prioritized. He advocated for eradicating all forms of social inequality including casteism and gender discrimination to ensure an impartial and equitable society for all. He emphasized the importance of economic growth and development to improve the lives of all citizens and create a strong and prosperous nation. He believed that despite the partition India and Pakistan could maintain cordial relations and cooperate on issues of mutual interest. However, Ambedkar's vision was tempered by caution and concerns. He worried that the "two-nation theory" could cause the way for religious majoritarianism and discrimination against minorities. He was anxious that Pakistan might become a weak and unstable state, vulnerable to internal conflicts and external threats. He deeply concerned about the fate of minorities in Pakistan fearing their marginalization and possible oppression. He urged the Pakistani government to ensure the protection of the fundamental rights and

cultural identities of all minorities within the nation through 'Secular Constitution.'

Relevance :

Dr. Ambedkar's vision for Pakistan serves as a relevant guide for the challenges faced by new nations. His emphasis on secularism, social justice, economic development and minority rights remains relevant today, not only in Pakistan but also in many other parts of the world. While his hopes for a progressive and inclusive Pakistan may not have fully succeeded, his insights continue to offer valuable lessons for policymakers and individuals striving to build impartial and equitable societies. Dr. Ambedkar's perspective gives deeper understanding of the complexities of nation-building and the importance of promoting tolerance, inclusivity and respect for human rights for all communities. Dr. B.R. Ambedkar's thoughts on Pakistan offer insightful perspective on a critical period in Indian history. His analysis of the historical context, the rationale for partition and the future of Pakistan remains relevant today which encourages reflection on the challenges of nation-building and the importance of religious tolerance and cooperation. As India and Pakistan continue their journey as independent nations, the lessons from Ambedkar's

wisdom can guide them towards a future of peace and prosperity for all citizens.

Conclusion :

Dr. B.R. Ambedkar's thoughts on Pakistan were rooted in his commitment to social justice, equality and the protection of minorities. His skepticism about the viability of a nation formed on the basis of religion reflected his deep concern for the welfare of all citizens regardless of their religious affiliation. Dr. Ambedkar's perspective on Pakistan correlates with the challenges faced by religious and ethnic minorities in various nations around the world. Dr. B.R. Ambedkar's thoughts on Pakistan were complex, reflecting both his pragmatism and his deep concern for the well-being of all communities. He ultimately accepted the partition of India. But he remained concerned about its long-term consequences particularly for minorities. His thoughts on Pakistan remain relevant today, especially in the context of ongoing political and religious tensions in the region. His analysis of the historical context and the potential dangers of religious nationalism offer valuable insights into the complexities of nation-building and the challenges of managing religious diversity. While some may criticize Dr. Ambedkar's willingness to accept the partition, it is

essential to appreciate his pragmatism and understanding of the political realities of the time. His concerns about the fate of minorities in both nations continue to resonate today, highlighting the need for sustained efforts to ensure equality and justice for all citizens.

- Ms. Sujata Balvant Shirode

Sangamner Nagarpalika Arts,
D.J. Malpani Commerce & B.N.Sarda
Science College (Autonomous), Sangamner
Mob. 98229 74123

References :

Ambedkar, B.R. (2014). "Pakistan or the Partition of India." In V. Moon (Ed.), Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches (Vol. 8). Dr. Ambedkar Foundation.

Dr. B.R. Ambedkar Research and Documentation Centre (BRARDC). Retrieved from <http://www.bamu.ac.in/> Ministry of External Affairs, Government of India.

Retrieved from https://www.mea.gov.in/Images/attach/amb/Volume_01.pdf Keer, D. (1971). Dr. Ambedkar: Life and Mission (3rd ed.). Mumbai: PopularPrakashan.

Mishra, S.N. (Ed.) (2010). Socio-economic and Political Vision of Dr. B.R. Ambedkar. New Delhi: Concept Publishing Company.

Shodhganga. (Year). Title of the thesis or dissertation. Retrieved from <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/143134>

Integrating ICT in ECCE-Status, Challenges, and Prospects with Special Reference to Selected Schools of Patna

- Mohd Gufran Barkati¹

- Dr. Jarrar Ahamad²

- Md Arif Equbal³

Abstract : There was a time when we used to play with hand-made toys in our childhood. But, things have drastically changed. Now, we are living in an era where none of the people is untouched by the use of ICT. Children start using smartphones from their early Childhood. Parents use smartphones to entertain their children with different kinds of cartoons and rhyming videos. The use of Information and Communication Technology (ICT) is increasing in various fields, including Early Childhood Care and Education (ECCE). Kids are exploring the world by using smartphones and computers. The integration of ICT in ECCE has been growing rapidly. A wide range of digital tools and platforms being developed specifically for young children. This paper examines the current status and challenges of ICT integration at pre-primary level and highlights the prospects of ICT integration at the foundational stage in the light of NEP 2020.

Keywords : ICT, ECCE, NEP-2020

Introduction :

Kids are exploring the world by using smartphones and computers. Children start using smartphones from their early age and become highly acquainted with the use of ICT. Researches suggest that preschoolers become familiar with digital devices before they are exposed to books (Brody, 2015, & Hopkins et. al., 2013). It fosters a connection between children and the contemporary world, enhancing their awareness of life, goals, and the tools necessary to achieve their objectives. NEP 2020 emphasizes holistic approach to education, aligning with the principles of emerging technologies and early childhood education, which recognizes the importance of a child's early years in shaping their overall development and equip them as per the requirements of 21st century skills. A new 5+3+3+4 school structure of the policy incorporates ECCE as a foundational component starting at the age of 3. ICT offer engaging, interactive, and personalized learning experiences,

fostering cognitive development, creativity, and problem-solving skills (Plowman et al., 2010). The kinds of games and other activities available on the internet, making children smart and shaping their thought processes. However, the integration of ICT in ECCE is not so common in India. It is because Most of the pre-primary schools, especially those situated in remote areas, lack internet connectivity and essential IT resources necessary for the implementation of modern educational technologies.

The present paper is a report of the study taken up to find out the status, challenges and prospects of ICT integration in five selected pre-primary schools and anganwadi centers of district Patna, Bihar, i.e. St. Johnson School, Drona Gurukul Vidyapeeth, Rizvi Foundation school, Kids Garden, and Anganwadi Neora.

The following objectives were framed for the study:

1. To find the status of ICT in selected schools and centers of ECCE.
2. To study the challenges faced by teachers during the use of ICT in classroom.
3. To examine the prospects of integrating ICT at foundational stage in the light of NEP 2020.

The required information for the objective 1&2 was collected from the selected schools and centers of the district by conducting an interview with the staff and administration of the respective schools. The original policy document was used as a main source for examining the prospects of ICT integration at foundational stage in the light of NEP 2020. Findings of the study were as follows:

Status of ICT in pre-primary Schools of Patna, Bihar: The given table indicates that St. Johnson School has 3 sets of computers but no projector, Drona Gurukul Vidyapeeth 15 sets of Computers with only 1 projector, Rizvi Foundation School has 5 sets of computers and 1 projector, Kids Garden has only 1 set of computers with a projector, and Anganwadi center neither has the computer nor the projector. Regarding the availability of software, all the institutions are using only free software. Internet connectivity is not available in all the schools, teachers use their personal hotspot wherever they require internet. Teachers use the available ICT tools to engage the students, make the complex concepts easy to understand, and develop interest among learners. They make use of short stories, rhymes, and sounds with the help

of ICT for the language development of children.

Table-1. ICT Facilities Available in Pre-primary Schools, Patna.

Schools	Computers & Projectors	Software	Internet Connectivity
St. Johnson School, Patna	3(C), 0 (P)	Free Software	N/A
Drona Gurukul Vidyapeeth, Patna	15 (C), 1 (P)	Free Software	N/A
Rizvi Foundation school, Neora, Patna	5 (C), 1 (P)	Free Software	N/A
Kids Garden, Patna	1 (C), 1 (P)	Free Software	N/A
Anganwadi, Neora Bazar, Patna	N/A	—	N/A

Challenges faced by teachers of pre-primary schools during the use of ICT: Almost all the teachers have basic knowledge and understanding of ICT integration in the teaching-learning process except those who are working in Anganwadi Centers. This is because they do not have much exposure to digital tools as compared to the other selected institutions. Some of the teachers find it difficult to prepare age-appropriate digital resources for children in the early stages of education. The dynamic nature of technology, aligned with the evolving needs of learners, demands continuous training to update the required skills. However, some teachers reported that obtaining permission or leave from their employer is often an obstacle to them for the same. Additionally, the time required to create digital learning resources, such as PowerPoint presentations, short

stories, and rhyming videos, poses another challenge. Moreover, the unavailability of internet access further compounds these issues, limiting the potential for interactive and engaging digital learning experiences in pre-primary classrooms.

Prospects of ICT integration for foundational stage in accordance with NEP 2020: NEP 2020 highlights the importance of integrating ICT across all educational levels, particularly at the foundational stage, to provide intriguing and age-suitable learning experiences.

1. Inclusive Digital Access : The NEP 2020 acknowledges the significance of inclusivity, stating the importance of granting every vernacular languages. This highlights the provision of equal chances for children from diverse linguistic backgrounds to gain from technological advancements in their early education.

2. Transformative Learning Environments : The National Education Policy of 2020 acknowledges the immense capacity of technology to transform conventional instructional approaches, thereby fostering a more individualized and flexible learning experience that caters specifically to the

distinct requirements and preferences of young learners.

3. Holistic Development: NEP 2020 aims at incorporating technology into early childhood education, in order to provide a well-rounded learning experience that surpasses academic knowledge and enhances the overall development and welfare of young learners.

4. Teacher Professional Development : The policy highlights the importance of teacher training and professional development programs to enhance digital literacy and pedagogical skills, ensuring that educators are well-equipped with basic digital skills necessary for the integration of technology into the foundational education curriculum.

5. Digital Infrastructure and Connectivity : NEP 2020 identifies robust digital infrastructure and improved connectivity as a priority. Solving internet accessibility issues becomes vital towards ensuring that every corner of the nation benefits from technological advancements thereby reducing the digital divide.

Conclusion : Findings of the study reveals evolving landscape of early childhood education in the digital age,

emphasizing children's early exposure to ICT and the transformative potential highlighted in NEP 2020. Despite the benefits, the integration of ICT faces challenges in pre- primary schools, particularly in remote areas lacking essential infrastructure. The study in Patna, Bihar, exposed varying ICT facilities, with limited resources, teacher training gaps, and hurdles in obtaining permission for development. The absence of internet connectivity hampers interactive and engaging digital learning experiences. NEP 2020 provides a promising framework, advocating inclusivity, transformative learning, holistic development, teacher training, and improved digital infrastructure. Bridging the gap between policy intent and on-the-ground challenges necessitates collaborative efforts to ensure effective ICT integration in pre-primary education, fostering a future-ready generation.

- Mohd Gufran Barkati¹
- Dr. Jarrar Ahamad²
- Md Arif Equbal³

1, 2 Assistant Professor,
Dept. of Education and Training, MANUU,
Hyderabad 3 P.G. Scholar,
Dept. of Education
and Educational Technology,
University of Hyderabad.
Mob. 90441 45228

References :

Brody, J. E. (2015). Screen addiction is taking a toll on children. The New York Times, 6. Retrieved from https://stratus.pnbhs.school.nz/pluginfile.php/20976/mod_resource/content/1/Screen%20Addictio%20Is%20Taking%20a%20Toll%20on%20Children.pdf

Donohue, C. (2019). Fred Rogers. Exploring Key Issues in Early Childhood and Technology: Evolving Perspectives and Innovative Approaches, 20. Retrieved https://www.google.co.in/books/edition/Exploring_Key_Issues_in_Early_Childhood/cTuhDwAAQBAJ?hl=en&gbv=0

Hopkins, L., Brookes, F., & Green, J. (2013). Books, Bytes and Brains: The Implications of New Knowledge for Children's Early Literacy Learning. Australasian Journal of early childhood, 38(1), Retrieved 23-28. from <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA328418382&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=18369391&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E957809fd&aty=open-web-entry>

MHRD, GoI. (2020). National Education Policy 2020), Government of India. Retrieved from https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

Plowman, L. Plowman L, McPake, J., Stephen C.(2010). The Technologisation of Childhood? Young Children and Technology In the Home. Children and Society 24 (1) 63-74. Retrieved from <https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/1935/1/Plowman%20et%20al%20Technologisation%20of%20childhood.pdf>

शिक्षा और जागरूकता : डॉ. अम्बेडकर

— डॉ. ललिता कौशल

शोध सार : शिक्षा द्वारा मनुष्य के अंतर में निहित उन शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना नितान्त असंभव है। शिक्षा पूरे संसार को प्रगति पथ पर लाने वाली एकमात्र प्रक्रिया है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति वहां के शिक्षा क्षेत्र पर निर्भर होती है। मनुष्य को सुव्यवस्थित तथा अच्छे ढंग से जीवन गुजारना है, तो उसे शिक्षित होना अनिवार्य हो जाता है।

शब्द संकेत : शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, वर्ण—व्यवस्था, संगठन

सामाजिक चिंतकों ने मनुष्य के जीवन में शिक्षा को अनिवार्य मानते हुए कहा है कि शिक्षा से ही मनुष्य का विकास होता है। उसी के माध्यम से वह संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धियों को प्राप्त करता है, लेकिन भारतीय समाज में वर्ण—व्यवस्था के कारण अस्पृश्य

जातियों के रूप में समाज के एक बड़े समुदाय को शिक्षा और ज्ञान से पूरी तरह वंचित रखने का षडयंत्र किया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने वंचित वर्ग को इस षडयंत्र से बाहर निकालने का अथक प्रयास किया। वे शिक्षा को एक हथियार मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य अधिक शक्तिशाली हो जाता है। शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बुद्ध ने भी कहा था 'सारे दुखों का कारण अज्ञानता है।' ¹ अज्ञानता के कारण ही मनुष्य पाप—पुण्य, भाग्य—भगवान, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, ऊंच—नीच तथा छुआछूत के घेरे में रहता है तथा दुखी होता है।

शोषित और अस्पृश्य वर्ग के मसीहा डॉ. अम्बेडकर ने शोषित समाज को उचित मानवीय अधिकार दिलाने और अज्ञान के अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहेब ने दलितों के

पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनकी अशिक्षा को माना है। अशिक्षित होने के कारण भारतीय दलित न तो अपने विरुद्ध ब्राह्मणों द्वारा रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके, बल्कि इस शोषण को अपनी नियति मानते रहे। बाबा साहेब ने इस तथ्य को गहराई और गंभीरता से समझा और दलित समाज को अपने विचारों से प्रोत्साहित तथा प्रेरित करके दलित अस्मिता से सही पहचान कराने का प्रयास किया। उनके अनुसार शिक्षित हुए बिना दलित जीवन में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। उनके द्वारा दिए गए त्रिसूत्र (शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो) में भी शिक्षा सबसे पहला सूत्र है, जिसके बिना संगठित होना और संघर्ष करना संभव नहीं है।

शिक्षा यदि सर्व-जन-सुलभ हो तो एक बात है, लेकिन भारत के समाज में ज्यादातर ऐसा नहीं रहा है। यहां प्राचीन काल में चातुर्वर्ण व्यवस्था लागू रही है। उस व्यवस्था में शिक्षा वर्ग-शिक्षा थी। उसमें शुद्र और अन्त्यज को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यह मनाही साफ-साफ धर्म ग्रंथों के संस्कृत श्लोकों में लिखकर की गई थी। डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं, 'शिक्षा एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी। यह कभी भी बहुजनों का अधिकार और अवसर नहीं रही। वस्तुतः चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में एक ही वर्ग शिक्षा प्राप्त कर सकता था और बाकी जनता इससे वंचित रखी गई थी।'²

डॉ. अम्बेडकर यह भी मानते थे कि भारत में अंग्रेज सरकार की शिक्षा नीति में साम्प्रदायिक संतुलन रहा है। उन्होंने गवर्नर जनरल को बताया था कि इसी साम्प्रदायिक नीति के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को समान रूप से तीन-तीन लाख रुपए सालाना सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। इसी तर्क पर उन्होंने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए अनुदान मांगे थे। अपनी पुस्तक 'स्टेट्स एण्ड माइनरिटीज' में उन्होंने अनुसूचित जातियों की सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा और विदेशी शिक्षा के लिए अलग-अलग धाराएं रखी थीं। गवर्नर जनरल के सामने अनुसूचित जातियों की

शिकायतें रखते समय उन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में इन जातियों के सदस्यों के रूप में दो प्रतिनिधि रखने की मांग भी रखी थी।³

आज भारत वर्ष में शोषित और पिछड़े लोगों में जो भी प्रगतिशील चेतना जागृत हुई है, उसका आधार बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी विचार और कार्य ही हैं। उन्होंने शिक्षा को जीवन में बहुत महत्त्व दिया है। स्वयं उन्होंने अपने समय की विश्व की सर्वोच्च शिक्षा पाई थी। बाबा साहेब ने अपने भाषणों में पुस्तकों में व लेखों में यह स्वीकार किया है कि शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है। शिक्षा के महत्त्व को स्वीकारते हुए उन्होंने उपेक्षित वर्ग को संदेश दिया था 'शिक्षा ही प्रगति का वह द्वार है जिसके खुलते ही विकास के अन्य सभी द्वार अपने आप खुल जाते हैं।'⁴ इसमें कोई शक नहीं कि आज भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वह शिक्षा द्वारा आई जागृति का ही परिणाम है।

अस्पृश्य लोगों के उद्धार के लिए डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि पिछड़े व शोषित वर्ग में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जागृति आए। बाबा साहेब ने सबसे अधिक जोर शिक्षा प्राप्त करने पर दिया। शिक्षा मनुष्य की एक विशेष योग्यता है और समानता की मंजिल के पथ पर ले जाने वाली प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि जिस समय डॉ. अम्बेडकर अपना गहन अध्ययन-मनन कर रहे थे, उस समय शोषित-पीड़ित समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। समाज अशिक्षित था। उन्होंने अनुभव किया था कि समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। शिक्षित व्यक्ति ही एकता के सूत्र में बंधकर संगठन का निर्माण कर सकते हैं। उनका मानना था कि जो समाज संगठित रहता है, वह किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उन्होंने वंचित समाज में शिक्षा के विस्तार के लिए 'पीपुल्स एज्युकेशन सोसायटी' की स्थापना की तथा इसके माध्यम से मुम्बई और औरंगाबाद में कॉलेज प्रारंभ किए। शोषित वर्ग के उत्थान के लिए पत्र-पत्रिकाओं तथा अखबार आदि का संपादन एवं प्रकाशन किया,

जिनमें साप्ताहिक 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', 'जनता' आदि प्रमुख हैं।

डॉ. अम्बेडकर एक समाज सुधारक, साहित्य के अनन्य साधक, समता, बंधुत्व तथा मानवता के पक्षधर और दलितों के मुख्य प्रेरणास्त्रोत हैं। उन्होंने समाज सुधार का काम 9 मार्च, 1924 से आरंभ किया। उन्होंने दामोदर हॉल मुम्बई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' स्थापित की। सभा के मुख्य उद्देश्य—1. शोषित वर्ग को शिक्षित करना, 2. शिक्षा के प्रचार—प्रसार के लिए हॉस्टल खोलना या दूसरे योग्य ढंग को अपनाना, 3. दलित वर्गों के लिए वाचनालय, समाज केन्द्र और विद्या केन्द्र स्थापित करके संस्कृति का प्रचार करना, 4. उद्योग और कृषि स्कूलों द्वारा उनकी आर्थिक दशा उन्नत करना एवं सुधारना, 5. पिछड़े वर्गों में सभ्य जीवन प्रसार के लिए पुस्तकालय, सामाजिक केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना।⁵ जनवरी, 1925 को 'हितकारिणी सभा' ने पिछड़े व शोषित छात्रों के रहने के लिए सोलापुर में एक हॉस्टल खोला, सभा विद्यार्थियों के कपड़ों, पुस्तकों, निवास तथा भोजन का भी प्रबंध करती थी। सभा ने उन छात्रों में विद्या और ज्ञान के प्रति स्नेह उत्पन्न करने के लिए एक अन्य संस्था स्थापित की। सभा के अनुसार छात्रों ने 'सरस्वती विलास' नामक एक मासिक पत्र भी आरंभ किया। बाबा साहेब ने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' दलित वर्ग संस्थान बंबई की ओर से बंबई प्रेसीडेंसी में दलित जातियों के हितों की अल्पसंख्यकों के रूप में रक्षा किए जाने सम्बंधी उपायों तथा प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत उन्हें सुनिश्चित करने हेतु कड़ा संघर्ष किया। वे दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के माध्यम से संरक्षण दिलाने का अभियान चला रहे थे। सामाजिक विषमताओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था—सभा तभी संतुष्ट होगी, जब दलित जातियों के सभी हितों की रक्षा होगी। सभी अल्पसंख्यक जातियों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार की आवश्यकता है। सभा देश के नागरिकों का राजनीतिक महत्त्व के आधार पर श्रेणीकरण करने पर विक्षोभ प्रकट करती है। इससे अधिक सुरक्षित और अन्य कोई नियम नहीं हो सकता

कि जातियों को राजनीतिक रूप से समान महत्त्व दिया जाए।⁶ दलित वर्गों की सभी समस्याओं पर अम्बेडकर ने न केवल ध्यान केन्द्रित किया, बल्कि दलित जातियों के अधिकारों के लिए प्राण—प्राण से संघर्ष किया। सामाजिक—धार्मिक अत्याचारों का पर्दाफाश किया कि कैसे दलितों को नदी—तालाबों तक का पानी पीने से रोका जाता है। दलित बच्चों को सवर्ण बच्चों से स्कूल में दूर बैठाया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत की सामाजिक व्यवस्था के प्रति विरोध किया। अस्पृश्यों को शिक्षा का पाठ पढ़ाकर मानवाधिकार दिलाने का बीड़ा उठाया। अम्बेडकर को इस सामाजिक व्यवस्था के विरोध में अपना पद भी त्यागना पड़ा था। उन्होंने इस तरह को अमानवीय घटनाओं को महसूस करते हुए कहा था—'जब मेरे जैसा उच्च शिक्षा प्राप्त योग्य व्यक्ति भी इस व्यवस्था में अस्पृश्य माना जाता है, तो उन लाखों—करोड़ों अस्पृश्यों की दशा तो और भी गई गुजरी होगी जो अशिक्षित व असभ्य हैं। उनकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है।'⁷

'थॉट्स ऑफ पाकिस्तान' के पहले संस्करण के टाइटिल पृष्ठ पर डॉ. अम्बेडकर ने यह कोटेशन उद्धृत किया है—'More brain, O lord, more brain! or we shall mar, utterly this fair garden we might win'⁸ एक कहावत है, 'जो कौमें मरना नहीं जानती वे जीना भी नहीं जानती।' इसी प्रकार जो कौमें पढ़ना नहीं चाहती वे जीवित ही नहीं रहतीं, क्योंकि जीने के लिए युक्ति चाहिए, युक्ति के लिए मस्तिष्क, मस्तिष्क के लिए ज्ञान और ज्ञान के लिए अध्ययन। इस कथन को डॉ. अम्बेडकर द्वारा उद्धृत उक्त कोटेशन के साथ पढ़ने पर वह चाबी मिल जाती है, जो जीवन संघर्ष की राह के हर दरवाजों को खोलती हैं। अपने हिस्से का अधिकार पाने के लिए बलिदान होने का जज्बा चाहिए और उसके लिए आवश्यक तार्किक हथियार है शिक्षा। बाबा साहेब ही ऐसे विचारक हैं, जिन्होंने अपने विचारों को स्वयं लिपिबद्ध किया है और प्रचुर मात्रा में उनका साहित्य उपलब्ध भी है।

अस्पृश्य समाज को उनके अधिकार दिलाने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने दलितोद्धार आंदोलन भी शुरू किया। उनका इस आंदोलन का मुख्य ध्येय शिक्षित होकर स्वयं के आत्मनिर्णय द्वारा प्रभावशाली ढंग से चलाये जाने का था। उनका मानना था कि किसी भी समुदाय का कल्याण बाहर के लोगों द्वारा कभी संभव नहीं है। बाबा साहेब ने एक नारा बुलंद किया 'आत्म सहायता ही सबसे उत्तम सहायता है।'⁹ इस प्रकार अपने उद्धार के लिए स्वयं शोषित व अस्पृश्य लोगों को शिक्षित होकर आगे आने का यह उनका आह्वान था।

बाबा साहेब उपेक्षितों और पिछड़ों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना चाहते थे। 'बहिष्कृत भारत' नामक पत्रिका के माध्यम से ही कोने-कोने में अपने क्रांतिकारी विचार उन तक पहुंचाए और उनमें जागृति पैदा की। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अधिकार भी मांग कर नहीं छीन कर लेने की शिक्षा दी। उन्होंने अस्पृश्यों को एक कांफ्रेंस में कहा—'आप आध्यात्मिकता की धर्मांध बातों में न फंसें, क्योंकि इन्हीं बातों ने आपको शोषित बनाया है। भाग्य में विश्वास मत करो, अपनी शक्ति में विश्वास करो। स्वाभिमानी लोग विचारों से समझौता नहीं करते। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बढ़कर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं होता।'¹⁰

डॉ. अम्बेडकर ने हर सम्मेलन में अपने भाषणों में दलितों को अपने उद्धार के लिए स्वयं सुधरने का आह्वान किया और उन्हें समझाया कि घृणित व गंदे काम छोड़ें, साफ-सफाई से रहें तथा अपनी दीनता त्याग कर पुरुषार्थी बनें। मृत पशुओं का मांस खाना बंद करें। मदिरा व अन्य नशे की लतों से अपने आपको बचायें। अन्याय होने पर उसका खुलकर प्रतिकार करें और संघर्ष करें। सबसे अधिक ध्यान स्वयं को जागृत करने एवं बच्चों को शिक्षित बनाने पर दें।

सन् 1947 में भारत आजाद हो गया और स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए जिस समिति का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर को

बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान में समता और समानता को सबका मौलिक अधिकार घोषित कर, सबको शिक्षा का समान अधिकार और दलित जाति को संसद और विधानसभाओं के साथ सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की। जिसका परिणाम यह हुआ कि दलित लोग पढ़-लिखकर सरकारी नौकरियों में ही नहीं, संसद और विधानसभाओं में भी आने लगे, जिससे हक की लड़ाई और तेज हुई। बाबा साहेब के क्रांतिकारी व्यक्तित्व एवं कृतित्व से दलित वर्ग में अपूर्व जागृति उत्पन्न हो गई थी। दलित वर्ग का उद्धार करने और समानता का अधिकार दिलाने के तत्कालीन सरकार को भी उन्होंने विवश कर दिया था। इसके लिए सरकार को दलित वर्ग के हित रक्षार्थ कानून बनाने पड़े। साइमन कमिशन के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था—'अछूतों की समस्याओं को हिन्दुओं से न जोड़ा जाए। अछूत सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः शोषित एवं दलित हैं। इन्हें सैकड़ों वर्षों से शोषित पीड़ित एवं दलित रखा गया है। इनके लिए शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए हैं। ये इंसानियत रूपी हैवानियत की जिंदगी के रूप में पशुओं की भांति इधर-उधर विचरण कर रहे हैं।'¹¹ डॉ. अम्बेडकर को यह अहसास था कि दलित बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल होता था। उनके लिए उन्होंने रात्रि स्कूल शुरू किए ताकि दिन में काम करने के बाद पढ़ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ें।

डॉ. अम्बेडकर की प्रेरणा से अस्पृश्य समुदाय पढ़ने लगा और वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर अपनी दयनीय स्थिति के बारे में सोचने लगा जिनको प्रस्थापित व्यवस्था ने वंचित और गूंगा बनाकर रखा था, वे संघर्ष की भाषा बोलने लगे। अम्बेडकरवादी विचारों को धारण करके लोग मानवीय मूल्यों पर आधारित क्रांतिकारी साहित्य का निर्माण करने लगे। बाबा साहेब के संघर्ष से ही वंचित समाज को लेखन की प्रेरणा मिली। आज दलित लेखन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बनाने में उनकी विचारधारा के आधार पर ही सफल रहा है।

वास्तविकता तो यही है कि जो डॉ. अम्बेडकर को

एक बार पढ़ लेता है, वह बार-बार पढ़ना चाहता है। बाबा साहेब जिनके लिए लड़े उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनकी तरह तीक्ष्ण तार्किक मेधा शक्ति की ओजस्वी एवं सक्रिय ऊर्जा चाहिए। बाबा साहेब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्रचुर साहित्य हमारे पास है। भविष्य का रास्ता इसी के पन्नों से होकर गुजरता है। इसलिए इसको पढ़ने और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा देते रहें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः नारकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। डॉ. अम्बेडकर ने बार-बार अस्पृश्यों को इसी बात के लिए प्रेरित किया है कि शिक्षा ही हमारी उन्नति का महत्त्वपूर्ण रास्ता है और इसी से हमारी अस्मिता की सही पहचान हो सकती है। शिक्षा से बराबरी की आकांक्षा तो पैदा होती ही है, साथ ही यह धारणा भी समाप्त होती है कि प्रतिभा जन्म-जात या केवल विशेष वर्ग के पास ही होती है। यदि बाबा साहेब की तरह ही वंचित और पिछड़े वर्ग के सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं एवं शिक्षा के महत्त्व को समझें तो समाज में उपेक्षितों की हैसियत बढ़ेगी और उनके विकास का रास्ता खुलेगा।

— डॉ. ललिता कौशल

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सांध्यकालीन अध्ययन विभाग, शिमला
मोबा. 94592 15692

संदर्भ :

1. बाबूराव बागूल, दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान, पृ. 247
2. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खंड-2, पृ. 472
3. बी. आर. अम्बेडकर, स्टेट्स एण्ड माइनरिटिज, पृ. 36
4. कृष्णदत्त पालीवाल, डॉ. अम्बेडकर और समाज व्यवस्था, पृ. 16
5. रामलाल विवेक, डॉ. अम्बेडकर जीवन और आदर्श, पृ. 57
6. कृष्णदत्त पालीवाल, डॉ. अम्बेडकर और समाज व्यवस्था, पृ. 111
7. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खंड-2, पृ. 132
8. मूलचंद सोनकर, दलित विमर्श विकल्प का साहित्य, पृ. 62
9. रामलाल विवेक, डॉ. अम्बेडकर जीवन और आदर्श, पृ. 47
10. भीमराव अम्बेडकर, दलितोद्धार के मूलाधार शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता पृ. 113
11. डॉ. नरेन्द्र सिंह, दलितों के रूपांतरण की प्रक्रिया, पृ. 104

Employee Relations and HRM : Critical Role in Fostering Sustainability in MSME Sectors

- Dr. Sudipta Adhikary

Abstract

Purpose : The purpose of the research is to comprehend how MSME enterprises in India evaluate their commitment to sustainability in connection to employee relations and HRM practices. This paper introduces a theoretical framework called "Awareness, Action, Comprehensiveness, and Excellence (AAACE)" to convey the remedies and practices embraced by MSME industries in achieving their sustainability initiatives.

Methodology : This study employed a cross-case study approach to analyse workers' and owners' opinions in MSME units in Kolkata and adjacent regions to determine how industrial relations and HRM practices foster the level of sustainability commitment.

Findings : The research proposed a framework with four stages "Awareness, Action, Comprehensiveness, and Excellence"—that captures HRM practices as embraced by MSME enterprises to cultivate their commitment towards sustainability.

Social Implications : MSME sector units are creating vibrant contributions towards the emerging Indian economy. When it comes to the question of safe employment and sustainability, quality jobs, inclusiveness, productive employment, safe and secure work conditions, opportunities to work and quality of work life seem to be driving parameters of employee growth.

Key Words : HRM, quality job, inclusiveness, MSME, AACE

1. Introduction

Over the past decade, 'commitment to sustainability' has been the subject of extensive academic investigation. The meaning of this term has been examined from several angles and explained in several ways. This study has adopted "commitment to sustainability," an idea provided by Jansson et al. (2017, p.71). The economic, social, and environmental aspects of this idea about all essential business activities have been examined.

1.1 Theoretical Discussion

The UN Conference on Sustainable Development, 2012 at Rio de Janeiro brought the concept of sustainable growth. It was adopted that all the goals must be supported by the actions of developed countries. The MDGs focused

mainly on problems in developing and poor nations but SDGs include developed nations also. MDGs assumed a "One size for all" strategy.

2. Study Objectives

a. To find whether decent work indicators are satisfactorily applied in MSME sectors in selected districts of West Bengal.

b. To identify the proper HR strategy required for MSME sectors considering a decent work agenda (Goal Number 8) in selected districts of West Bengal in the transition of change.

3. Methodology

The study inter alia proposes to unearth the possibilities of adoption of proper HR strategy required for MSME sectors considering decent work agenda (Goal Number 8) in chosen areas of West Bengal. Again 398 participants from 28 companies from Kolkata and Howrah in the MSME sector are included in the sample frame.

3.1 Collection of Data

Over the course of six months, interviews with key internal stakeholders in strategic roles were performed at 28 MSME units.

3.2 Analysis of Data

Some of the major challenges confronted by MSME enterprises

include lack of adequate credit and capital, poor and inadequate infrastructural facilities, inadequate access and marketing linkages, technological obsolescence and inadequate application of new technology, lack of skilled human resources, dilatory and cumbersome regulatory practices for clearance and poor adaptability to emerging international trends.

3.3 Problem of Finance (SDG Goal 8 indicator):

One of the greatest challenges which constrain the growth of MSMEs in chosen areas relate to inadequate capital and credit facilities. Easy and timely access to credit is a crucial factor in the development and growth of enterprises.

3.4 Quality Jobs (SDG Goal 8 indicator):

Deficiencies in the infrastructure and poor support facilities marked by inadequate access to basic facilities like water, power supply, road/rail connectivity etc. adversely affect this sector and contribute to enhancing their operational cost by rendering the MSMEs less competitive in challenging market situations.

3.5 Public Policy (SDG Goal 8 indicator):

Poor marketing linkages characterized by inadequate Government support and patronage, lack of adequate marketing infrastructure / network facilities continue to be a greater challenge for marketing and sales of MSME products.

3.6 Sustainable Employment (SDG Goal 8 indicator):

Non-availability of skilled workforce and better managerial/entrepreneurial expertise at an affordable cost near the location of enterprises is another such big challenge for the MSMEs in our country.

3.7 Resource Efficiency (SDG Goal 8 indicator):

Most of the industries today require application of advanced technology in their operations whereas in the Indian context continuance of low-technology base results in low productivity by making these enterprises uncompetitive in the ever-widening market contexts.

3.8 Lack of Development-Oriented Policy (SDG Goal 8 indicator):

Cumbersome disbursement and dilatory regulatory clearances relating to sanction and of loans from commercial banks, collateral securities/guarantees, for construction permits, resolving

insolvency and taxation, etc. continue to be the constraining factors for many MSMEs.

4. Findings:

A new conceptual framework is proposed in the study, giving four dimensions that explore how employee interactions and HRM practices might fortify the dedication to sustainability among MSMEs.

a. Awareness :

A growing commitment to sustainability begins with raising one's level of consciousness. It is connected to the CEO briefing the staff on the company's plans. The company's priorities and the sustainability-related actions that employees are expected to do can be gleaned from these. Awareness includes access, inclusion, and reorientation of sustainable HR practices.

b. Action

The second key finding from the case companies' data is the importance of taking the right steps to coordinate existing procedures with the management of sustainability agendas. Action includes upskilling and long-term development of human resources.

c. Comprehensiveness

The development of a comprehensive support structure to drive coordi-

nated efforts towards the construction of a 'holistic' culture emerged as a crucial component in motivating MSME companies to pursue sustainability over the long term. Comprehensiveness includes setting up of KRAS to focus on sustainability-driven competency development.

d. Excellence

There is a wealth of evidence in the data that shows how these example companies pursue excellence through the deliberate selection and execution of strategies and initiatives that maximize available resources. The success of a firm depends on its management taking a proactive, opportunity-oriented attitude.

5. Conclusion

The research findings suggest that HRM practices highlighted by the informality of leadership towards employees are vital to the formation of a company's dedication to sustainability. It is innovative and counterintuitive to utilize unconventional approaches to overcome power imbalances and information gaps work towards a shared objective and foster a culture of continuous learning and improvement.

- Dr. Sudipta Adhikary

Assistant Professor, School of Law,
Brainware University, Barasat, India
Mob. 82963 51796

References :

Ahlstrom, D., Bruton, G.D. and Yeh, K.S. (2008), "Private firms in China: building legitimacy in an emerging economy", Journal of World Business, Vol. 43, No.4, pp.385- 399.

Al-Ali, A.A., Singh, S.K., Al-Nahyan, M. and Sohal, A.S. (2017), "Change management through leadership: the mediating role of organizational culture", International Journal of Organizational Analysis, Vol.25, No.4, pp. 723-739.

Amui, L.B.L., Jabbour, C.J.C., de Sousa Jabbour, A.B.L. and Kannan, D. (2017), "Sustainability as a dynamic organizational capability: a systematic review and a future agenda toward a sustainable transition", Journal of Cleaner Production, Vol.142, No. 1, pp.308-322.

Atkinson, C., Mallett, O. and Wapshott, R. (2016), "You try to be a fair employer': regulation and employment relationships in medium-sized firms", International Small Business Journal, Vol. 34No.1, pp.16-33.

Bartram, T. (2005), "Small firms, big ideas: the adoption of human resource management", Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 43, No. 1, pp. 137-154.

A Study of Principals' Administrative Effectiveness and Their Institutional Academic Performance

- Dr. Mohan Lal 'Arya'
Professor
- Gaurav Kumar
Research Scholar

Abstract : The present research paper is a description of the Principals' Administrative Effectiveness and their Institutional Academic Performance in the important salient aspect of School Administration and Management. The study under this division : U.P. and C.B.S.E. Boards. This division is done to keep proper representation of schools from all areas. The total 68 secondary schools were selected randomly. The sample belongs 68 secondary schools from U.P. Board and C.B.S.E. The selection of the schools indicates the selection of principals and academic performance of that school. To get data on Principal's Administrative Effectiveness, "Administrative Effectiveness Scale" was administered on teachers of that school. So the 5 teachers were selected randomly from each secondary schools of the sample. All students of IIX classes were selected from 68 secondary schools for getting scores on "Institutional Academic Performance". The total

numbers of students were 8803.

Key Words : Principal, Teachers, Academic Performance, Effectiveness, Students. Introduction: - A sound administration is a sine qua non for any organization aiming at achieving its goals. Administration is the growth of skills in dealing with human relationship which constitute the essential knowledge of administration effectiveness. The difference between effectiveness and efficiency is that the test of effectiveness is the accomplishment of the common purpose of organization, while the test of the efficiency is the eliciting of the individuals will to co - operate. Administration denotes the ability of the administration to achieve the goals and objective of the organization .the discussion relates the administration which consist of the definitions, history and Background, administration effectiveness and how to be an effective administrator. Management procedure in any organization significantly influence how well organization often its goals and objective. Management procedures that are effective invariably foster the attainment of goals of the organization.

Need and Significance of the Study: -
In a school, the principal holds a key position and is the coordinating agency

the balance and ensuring the harmonious development of pupils. He has the ability to design such an organizational climate in his institution, which is conducive for the total personality development of the learners. His administrative ability affects teachers directly satisfy them, provides the freedom of work and affects students indirectly through the medium of teachers. Many researches have been done in this context as the effect of principal's leadership or administrative behaviour on the climate of the organization, teachers alienation etc. very few researchers have been conducted to look the direct impact of principals administrative behavior on students academic achievement. This was tried to know only that different types of administrative style keep an impact on students to gain more achievement or not. A set of desirable behaviours requires operating the functioning the school for a principal.

Objectives of the Study :-

1. To find out difference between the Institutional Academic Performance of Principal's with High Administrative Effectiveness and Low Administrative Effectiveness.
2. To find out difference between the Principal's Administrative Effectiveness

of U.P. Board and C.B.S.E. Board Secondary Schools.

3. To find out difference between the Academic Performance of U.P. Board and C.B.S.E. Board Secondary Schools.

Hypothesis :-

1. That there is no significant difference between the Institutional Academic Performance of the Principal's with High Administrative Effectiveness and Low Administrative Effectiveness.

2. That there is no significant difference between the Principal's Administrative Effectiveness of U.P. and C.B.S.E. Board Secondary Schools.

3. That there is no significant difference between the Institutional Academic Performance of U.P. and C.B.S.E. Board Secondary Schools.

Methods of the Study : The researcher has used the Ex-Post factor method in which an attempt is made to study the administrative effectiveness of the Principals of Secondary Schools.

Population and Sample : - The population for the study is consisted of the total number of Principals, Teachers and Students of all U.P. and C.B.S.E. Boards Secondary Schools of Moradabad District.

Statistical Techniques : - The researcher has used Pearson Product Moment techniques to calculate scores, to test. 't' test and 'f' test were also use to calculate scores.

Delimitations of the Study :- This study is delimited to rural and urban Secondary schools Students, Teachers and Principals of Moradabad District.

Analysis and Interpretation of Data :

Hypothesis-1 That there is no significant difference between the Institutional Academic Performance of the Principal's with High Administrative Effectiveness and Low Administrative Effectiveness.

Table No- 1
Institutional Academic Performance of Principal's with High Academic Effectiveness (HAE) and Low Academic Effectiveness (LAE)

	Group-A	Group-B
Mean on Institutional Academic Performance (IAP) Principal's with HAE and LAE (M)	267.88	242.41
SD on Institutional Academic Performance (IAP) with HAE and LAE (σ)	30.41	22.03
Numbers of Schools (N)	40	28
t – value – 5.42		
Table value -	df = 70 .01 - 2.65 .05 - 2.00	

In the table-1 it is clearly shows that the mean on Institutional Academic Performance (IAP) of Principals with high Administrative Effectiveness is having the mean score 267.88 and the mean on Institutional Academics Performance (IAP) of Principals with low Administrative Effectiveness (PAE) have the mean scores 242.41. SD for both the group is 30.41 and 22.03 respectively. The number of schools is 40 and 28 related to both groups. After applying the t- test (Independent group and large sample), the value observed as 5.42. The level of significance, given in the D table

at .01 levels is 2.65 and the significance level at .05 levels is 2.00. The number of schools is 68 but the researcher used 70 df for the convenience. This shows that the t- value of the both group is significant at both the levels of means difference between Institutional Academic Performance (IAP) of Principals with high Administrative Effectiveness and low Administrative Effectiveness.

Hypothesis-2 That there is no significant difference between the Principal's Administrative Effectiveness of U.P. and C.B.S.E. Board Secondary Schools.

Table No- 2
Principal's Administrative Effectiveness of U.P and C.B.S.E. Boards Schools

	Group-A	Group-B
Mean on Principal's Administrative Effectiveness (PAE) of U.P. and C.B.S.E. Schools (M)	127.21	124.21
SD on Principal's Administrative Effectiveness (PAE) of U.P. and C.B.S.E. Schools (σ)	9.25	16.67
Numbers of Schools (N)	39	29
t – value – 0.86		
df = 70		
Table value -		
.01 - 2.65		
.05 - 2.00		

In the table 2, it is clearly shown that the mean on Principal's Administrative Effectiveness (PAE) of U.P. board schools is 127.21 and the mean on Principal's Administrative Effectiveness (PAE) of C.B.S.E. board schools is 124.25. SD for both the group is 9.25 and

16.87 respectively. The numbers of Government and Public schools are 39 and 29. After applying the t-test (Independent group and large sample), the value observed is 0.86. The level of significance given in the table at .01 level is 2.65 and the significance level at .05

levels is 2.00. The df is considered 70. This shows that the t-value is not significant at both levels of mean difference between Principal Administrative Effectiveness of U.P. and C.B.S.E. Schools.

Hypothesis-3 That there is no significant difference between the Institutional Academic Performance of U.P. and C.B.S.E. Board Secondary Schools.

Table No- 3
Institutional Academic Performance of U.P and C.B.S.E. Boards Schools

	Group-A	Group-B
Mean on Institutional Academic Performance (IAP) of U.P. and C.B.S.E. Schools (M)	256.05	271.62
SD on Institutional Academic Performance (IAP) of U.P. and C.B.S.E. Schools (σ)	24.17	38.96
Numbers of Schools (N)	39	29
t - value - 1.898		
df = 70		
Table value -		
.01 - 2.56		
.05 - 2.00		

In the table-3, it is clearly shown that mean on Institutional Academic Performance (IAP) of U.P. schools is 256.05 and the mean on Institutional Academic Performance of C.B.S.E. schools is 271.62. SD for both the groups is 24.17 and 38.96 respectively. The numbers of U.P. board schools are 39 and C.B.S.E. board are 29. After applying t-test (Independent group and large sample), the observed value is 1.898. The level of significance given in table at .01 levels is 2.65 and the significance level of .05 levels is 2.00. The df is considered 70. This shows that the t- value of either of the groups is not significant at both the levels of mean difference. The difference

between Institutional Academic Performance of U.P. and C.B.S.E. Schools is not significant.

Findings/Result : It is clear that Principal is that direct force to motivate or make much healthy environment of the schools, where students can develop their potential at maximum level. This study shows that Principal's Administration affect the Academic Performance of Students. If a principal is high or more effective in his/her functioning of Administration, the Institution/school will get good performance in the form of high academic scores of students. The finding of this hypothesis-2 is that Administ-

ative behaviour of principals is same in U.P. and C.B.S.E. boards secondary schools. Both principals are performing a variety of behaviour. Therefore, it is not matter of principals' Administrative Effectiveness whether they are working in U.P. and C.B.S.E. boards schools. Both types of schools are administered by high and low administrative Effectiveness Principals. The finding of this hypothesis-3 is that Institutional Academic Performance is found similar in U.P. and C.B.S.E. boards secondary schools. The students of both groups of schools are same in their Academic

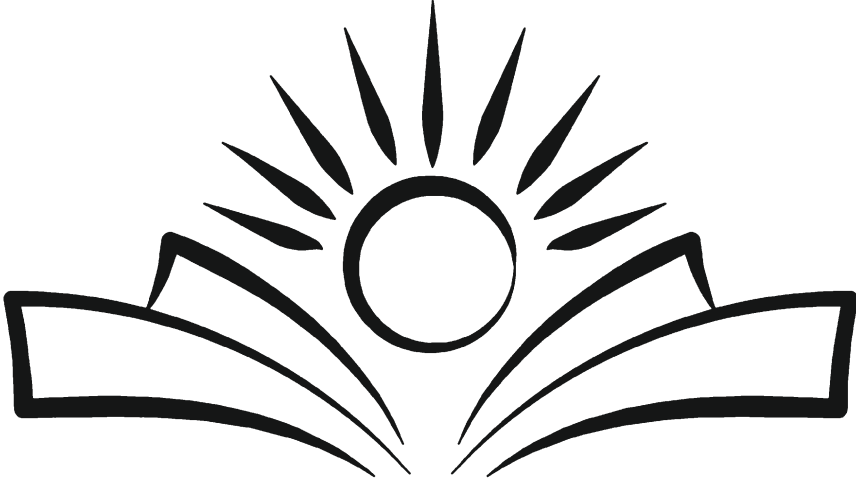
Performance. The students of these schools get the same level of academic scores. It is not necessary that students of U.P. and C.B.S.E. boards schools will achieve only high Institutional Academic Performance or low Institutional Academic Performance. These schools perform both high and low level of academic performance of their students.

- **Dr. Mohan Lal 'Arya' Professor**
Department of Education
IFTM University, Moradabad, U.P.
Mob. 8126543884

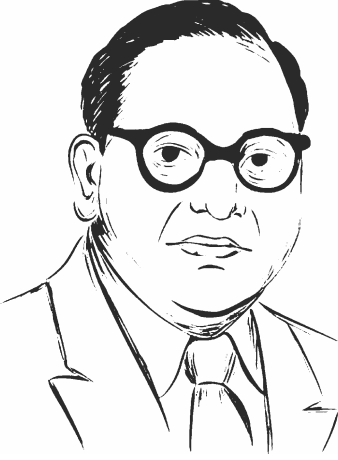
- **Gaurav Kumar**
Research Scholar
Department of Education
IFTM University, Moradabad, U.P.

References :

1. 'Arya', Mohan Lal (2014), "Educational Administration and Management" (Hindi), Surya Publication, Meerut.
2. Agarwal, Vidya (1993), "A study of Stress Proneness, Adjustment and Job-Satisfaction of Administrative Effectiveness of Principal", Fourth Survey of Educational Research.
3. Aphalwar, S. Manohar Rao (1996), "Evaluation of Administration of Secondary Schools of Adilabad and Karimnagar Districts of Andhra Pradesh with Special Reference to Headmasters", Indian Educational Abst. Issue-I, July.
4. Barnard, Chester I. (1964), "The Function of Executive", Cambridge, Mass, Harward University Press.
5. Deightan, Lec. C. (1971), "Encyclopedia of Education." Editor- in- chief, Vol.-3, The Machmillan Company & the free press, USAS.
6. E.G. Guba and Bidwell (1957), "Administrative Relationships", University of Chicago: Chicago Midwest Administrative Center.
7. Good, Carter V. (1959), "Dictionary of Education", 2nd ed., New York: McGraw Hill Book Company.
8. Jacob W. Getzels, James M. Lipham and Ronald F. Campbell, "Educational Administration As a Social Process", New York, Evanston and Landon: Harper and Row Publishers.
9. Lal, Dr. Mohan and Singh, Rajkumari (2018), "A Study of Principal's Administrative Effectiveness and His Institutional Academic Performance in Moradabad District", Unpublished Ph.D. Thesis, IFTM University, Moradabad.
10. National Policy on Education-1986, Ministry of Human Resource Development, Government of India (Deptt. Of Education), New Delhi.
11. Paul R. Mort (1946), "Principles of School Administration", New York, McGraw Hill.
12. Sears, Jesse B. (1950), "The Nature of the Administrative Process", New York, McGraw Hill.
13. Sharma, R. A. (2004) "Educational Administration and Management", Surya Publication, Meerut.
14. Steppen J. Knezevich (1984), Administration of Public Education, 4th Ed., Harper and Row Publishers, New York.



- यदि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। स्वास्थ्य, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलासफी बनाने से ही सफलता की शुरुआत होती है।
- अपनी अन्तरात्मा की आवाज को सोने-चांदी के सिक्कों से न तौलें।
- अंध विश्वास, अशिक्षा का पुत्र है। अज्ञानता के अंधेरे में ही अंधविश्वास का जन्म होता है।
- मन की शुद्धता व्यक्ति और समाज को एक नई दिशा और नया स्वरूप प्रदान करता है।
- जीवन में महत्वपूर्ण है - "शिक्षा और दीक्षा।"



- हमारे पढ़े-लिखे होने से सबकुछ हो गया, ऐसा नहीं है, शिक्षा के साथ-साथ मनुष्य के शील में भी परिवर्तन होना चाहिए। शील के बिना शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है।
- चरित्र और मानवता के बगैर एक शिक्षित इंसान पशु समान है।

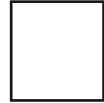
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

पंजीयन संख्या

RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में,



पत्र व्यवहार का पता :

20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

--	--	--	--	--	--

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुद्रित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार

जुलाई 2024